

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 562/2012/बांसवाडा
मैसर्स जगदम्बा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्रा.लि.
बांसवाडा

प्रार्थी

बनाम

उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर

अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अंजनी त्रिवेदी
सी.ए.
श्री एस.के. उपाध्याय
सहायक आयुक्त

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 28.10.2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 96/आरवैट/10-11 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 का आदेश दिनांक 17.11.2010 को पारित करते हुए आरोपित कर रु. 1320/- को रिवर्स किया है, जिसे यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मार्बल के वेस्टेज से हैण्डीक्राफ्ट आईटम (हस्तशिल्प) का निर्माण किया, जिसमें उसके द्वारा आई.टी.सी. क्लेम किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्बल के वेस्टेज से हैण्डीक्राफ्ट आईटम (हस्तशिल्प) का निर्माण को कर मुक्त माल की श्रेणी में मानकर आई.टी.सी.को रिवर्स कर आदेश दिनांक 17.11.2010 पारित किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2010 को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2011 पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. के प्रारम्भिक रोकड जमा (opening Balance) पर विचार नहीं किया गया है और अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गई है, जो

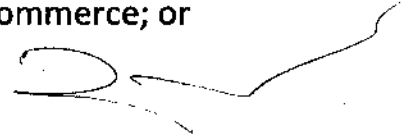
अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवसायी मार्बल के वेस्टेज से हैण्डिक्राफ्ट आईटम का निर्माण करता है जिस पर आई.टी.सी.अस्वीकार करना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों पर ध्यान दिये बिना आई.टी.सी. रिवर्स की गई है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से सहायक आयुक्त श्री एस.के. उपाध्याय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो मार्बल की खरीद की है, उससे मार्बल के हस्तशिल्प आईटम्स का निर्माण किया गया है तथा कर मुक्त माल के निर्माण हेतु खरीद गये माल पर आई.टी.सी.देय नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं विधिक उपबन्धों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में आई.टी.सी.रिवर्स किये जाने के प्रश्न पर निर्णय दिया जाना है। आई.टी.सी. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती है। इसलिए उक्त प्रश्न के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा 18 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. – (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "**except those as may be notified by the State Government,**" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or



(f) **"being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale"** in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

"(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed."

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases—

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or



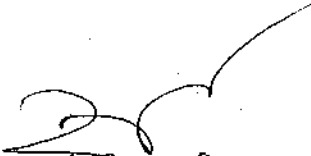
(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction , on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

(4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात निष्कर्ष दिया है कि "व्यवसायी ने जो मार्बल की खरीद की है, उससे ही यह मार्बल के आईटम (हस्तशिल्प आईटम) बनाये हैं। कर मुक्त माल के निर्माण हेतु खरीदे गये माल आई.टी.सी.देय नहीं है। यहां पर खरीद गये मार्बल से हस्तशिल्प बनाया गया है। अतः ऐसे में कर रिवर्स करना समुचित होने से व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है...।"

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित निष्कर्ष देते हुए अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार की गई है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2011 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य